आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 23.02.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित।
- सत्र के दौरान भू–कानून समेत कुल 10 विधेयक पारित किए गए, कुल 37 घंटे 49 मिनट चला सत्र।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
- प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के 156 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा।
- उत्तराखंड गृह विभाग ने यू०सी०सी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यविहीन जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

विधानसभा सत्र अनि□चतकाल स्थगित

उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पांच दिवसीय यह सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें 2025–26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी गई। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी अधिक है और उत्तराखंड के पहले बजट से 24 गुना बड़ा है।

सत्र के दौरान भूमि सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमाएं तय की गई हैं।

सत्र कार्यवाही –

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार कुल 37 घंटे 49 मिनट तक चला। सत्र के दौरान भू–कानून समेत कुल 10 विधेयक पारित किए गए। इनमें उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिये विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) संशोधन विधेयक और उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

इसके अलावा, जल प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम को संकल्प के रूप में पारित किया गया। सत्र के दौरान विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड 2024–25, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के विभिन्न लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट भी पेश की गईं।

बजट सत्र कार्यवाही–

इससे पहले, उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे सदन में पेश किया था।

बजट सत्र के दौरान विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली मीटर जंपिंग और ट्यूबवेल कनेक्शन में देरी को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विधायक काजी निजामुद्दीन ने बिजली विभाग के घाटे पर चिंता जताई।

परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोडवेज डिपो के घाटे और ड्राइवरों की कमी का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने आईएसबीटी को फिर से डिज़ाइन करने और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग बस अड्डे बनाने का सुझाव दिया।

अनुसूचित जनजातियों के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि बजट का केवल तीन प्रतिशत ही जनजातियों के लिए रखा गया है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जनजातीय निदेशालय के गठन की मांग की।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कडी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, पीएमओ तथा सूचना

और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा।

साइकिल रैल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देश पर पुलिस लाइन में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वयं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 20 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। इस रैली में 250 से अधिक साइकिल प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता शपथ के साथ हुई, जिसके बाद रैली पुलिस लाइन से आराघर चौक, ईसी रोड, राजपुर रोड, कैनाल रोड होते हुए काटबंग्ला पुल तक गई और फिर वापस पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंची।

तैनाती

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के 156 रिक्त पदों पर जल्द ही फैकल्टी तैनात की जाएगी। इससे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रिक्त पदों की समीक्षा की। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को मार्च 2024 में प्रोफेसरों व एसोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा था, जिसकी चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डॉक्टर रावत ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने को कहा, जिस पर एक माह के भीतर नियुक्तियों की सूची जारी करने का आश्वासन दिया गया।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में न्यूरो फिजिशियन और गैस्ट्रोलॉजिस्ट के नए पद सृजित करने और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

कार्रवाई की चेतावनी

उत्तराखंड गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यविहीन जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि विवाह पंजीकरण से बाहरी लोगों को उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र मिल जाएगा, जो पूरी तरह गलत है।
गृह विभाग ने कहा कि अफवाह फैलाना या गलत जानकारी प्रसारित करना कानूनन अपराध है। ऐसे व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यदि किसी को यूसीसी से संबंधित किसी भी प्रावधान पर संदेह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग से आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं।

स्लग–कृषि विज्ञान कांग्रेस समापन

पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्पन्न हुई। इस सम्मेलन में देश–विदेश के करीब चार हजार वैज्ञानिक, शोधकर्ता, छात्र और किसान शामिल हुए।

समापन समारोह के अवसर पर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए गहन चर्चा की गई। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सम्मान

उत्तराखंड के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और जड़ी–बूटी विशेषज्ञ डॉ. मायाराम उनियाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार देशभर के केवल तीन विशेषज्ञों को दिया गया, जिनमें डॉ. उनियाल भी शामिल हैं। उन्हें यह सम्मान आयुर्वेद और जड़ी–बूटी विज्ञान में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।

प्रकृति परीक्षण

केंद्रीय आयुष मंत्रालय के बेहद महत्वपूर्ण प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण में उत्तराखंड में डेढ़ लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। अभियान के तहत उत्तरकाशी के महीडांडा जैसे सीमांत इलाके में स्थित आईटीबीपी की पोस्ट तक भी आयुष टीम पहुंची और जवानों का प्रकृति परीक्षण किया। राज्य समन्वयक डॉ जेएन नौटियाल के अनुसार–विपरीत भौगोलिक स्थितियों के बावजूद डेढ़ लाख लोगों का उत्तराखंड में प्रकृति परीक्षण किया गया है। गौरतलब है कि देशव्यापी प्रकृति परीक्षण अभियान में पूरे देश में एक करोड़ लोगों के प्रकृति परीक्षण का लक्ष्य रखा गया था। अब तक लक्ष्य से ज्यादा एक करोड़ 29 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। इस अभियान में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉच किया है, जिसमें पंजीकरण कराने के बाद संबंधित व्यक्ति से बातचीत के आधार पर उसकी प्रकृति का निर्धारण किया जा रहा है। वात, कफ व पित्त की स्थिति का आंकलन करके संबंधित व्यक्ति की प्रकृति उसे बताई जा रही है। इसके साथ ही, आयुर्वेद चिकित्सक संबंधित व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुरूप आहार–विहार का परामर्श दे रहे हैं।